

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—सण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 70]

नई दिश्लो, रानिवार, भ्राप्रैल 30, 1983/वैशाख 10, 1905 NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983/VAISAKHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह सलग संकलन को रूप में रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भम एवं पुनर्वास मंत्रालय (भम विभाग)

नर्ड दिल्ली, 30 मप्रैल, 1983

सं० यू०-23013(8)/62-एल०डक्टयू०:-भारत के राजपत्त (असाधारण), भाग-I, खण्ड-1 तारीख 5 त्वम्बर, 1982 को प्रकाणित इस्विभाग के संकल्प सं०यू०-23013(8)/82-एल० डब्ल्यू तारीख 5 तवस्वर, 1982 में, कुछ और प्रस्ताव जोड़ दिए गए है और इन प्रस्तावों के साथ, उक्त संकल्प को निथमानुसार पढ़ा जाएगा।

सं कल्प

राजस्थान, उड़ीसा और विहार में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई है जो इन राज्यों से दिल्ली, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्रवास करने वाले उत्प्रवास श्रमिकों की कामकाज तथा रहन-महन की असंतोषजनक दशाओं के बारे में है। 140 GI/83

आन्द्र-प्रदेश से महाराष्ट्र विशेष रूप से बृहत्त बम्बई शहर को प्रवास करने वाले श्रामिको द्वारा अनुभव की गई सदृश कठिनाइयों को भी सूचित किया गया है। उत्प्रवास श्रमिको से संबंधित विभिन्त समस्याओं और कठिनाइयो पर श्रम-मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 21 अगस्त, 1982 को नई दिल्ली में हुई 11 राज्यों के श्रम मिववा की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था । यह मालुम हुआ कि अधिकाश राज्यों ने अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा गर्तें) अधिनियम, 1979 के अधीन नियमों की नहीं बनाया और अधिसूचित नहीं किया है जिस से उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का काम कठिन हो गया यह मालूम हुअ। कि इस बीच संबंधित राज्यों के अर्थात वह राज्य जहा मे श्रमिक जाते हैं और वह राज्य जहां वे जाने है, अधिकारियों की मंयुक्त टीम को प्रवासी श्रीमको समस्याओं के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठक हो सकतो है। यह भी सुझाव दिया गया कि कार्य-स्थलों का दौरा करके प्रवासी श्रमिकों की वास्पविक कार्य तथा रहन-सहन दशाओं के बारे में संयुक्त अध्ययन किए जाए ताकि उनकी कार्य तथा रहन-सहन दशाओं की प्रत्यक्ष जानकारी हो सके तथा विशिष्ट शिकायतों पर भी विचार किया जा सके। तदनुसार, केन्द्रीय तथा संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों महित संयुक्त अध्ययन टीमों को गठित करने का निर्णय किया गया है। अध्ययन टीमों का गठन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्न होंगे :---

2. गठेन:

संयुक्त अध्ययन टो० न'०-Т

 श्री एस०के० वास, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), बस्बई

सदस्य संयोजक

 आन्ध्र-प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि।

मदस्य

 महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

मदस्य

मंयुक्त अध्ययन टीम नं०-11

 श्री ओ०पी० सक्सेना क्षेत्रीय श्रमायुकतः (केन्द्रीय), चण्डीगढ़।

सदस्य-संयोजक

 बिहार सरकार, पटना ब्वाना नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

सदस्य

 उद्योसा सरकार, भुवनेश्वर द्वारा नाभित किया जाने वाला प्रतिनिधि

सदस्य

 राजस्थान सरकार, जथपुर द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

सर्वस्य

 पंजाब मरकार, चंडीगढ़ द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि ।

सदस्य

 हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ द्वारा नामित किया जाने वाला प्रेसिनिधि

सदस्य

 हिमाचल-प्रदेश सरकार, शिमला ब्रारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

सदस्य

 जम्मू व कश्मीर सरकार श्रीनगर द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

सदस्य

9. दिल्ली प्रणामन, दिल्ली द्वारा सदस्य नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि

- 10. पश्चिम बंगाल सरकार, कलकरता सदस्य द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिनिधि
- 11. मध्य-प्रदेश सरकार, भोषाल सदस्य द्वारा नामित किया जाने प्रतिनिधि
 - 3. संयुक्त अध्ययन टीमां के विनागर्थ विषय:---

उपर्युक्त संयुक्त अध्ययन टोम (I) और (II) प्रतिनिधि राज्यों का यथा-णोध दौरा करेंगी ताकि

- (i) उन प्रतिनिधिक राज्यों के कार्य-स्थलों का दौरा किया जा सके जहां प्रवासी श्रिमिक नियोजित हैं और जिनके बारे मे विशेष शिकायतें प्राप्त हुई है।
- (ii) प्रवासी श्रमिको की समस्याओं का, इन विभिन्ट शिकायतो के संदर्भ में, तुरंत अध्ययन किया जा सके
- (iii) प्रवासः की अन्य णिकायतों की, यदि कोई हो, (विणिष्ट णिकायनों के अतिरिक्त) तस्काल दूर करने के लिए सामान्य निरोक्षण किया जा सके।
- संयुक्त अध्ययन टीम नं०-[का मुख्यालय बम्बई और संयुक्त अध्ययन टीम नं०-[] का मुख्यालय चंडीगढ़ होगा।
- 5. दोनों टीमें अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय के मचित्र को यथा-मीध्र प्रस्तुत करेगी जिनमें प्रवासी श्रमिको की समस्याओं के यिणिष्ट उपचारों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

एस० वेन्कटरामानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 30th April,1983

No. U-23013 (8) /82-LW:—In this Department's Resolution No. U-23013(8)82-LW dated the 5th November, 1982, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, dated the 5th November, 1982, certain additions have been made and with these additions, the said Resolution will read as follows:

RESOLUTION

Complaints have been received from time to time from Rajasthan, Orissa and Bihar about the unsatisfactory working and living conditions of migrant workers migrating from these States to Delhi, Jammu & Kashmir, Punjab, West Bengal, Madhya Pradesh, Haryana and Himachal Pradesh. Similar difficulties faced by labourers migrating from Andhra Pradesh to Maharashtra, particularly to Greater Bombay city area have also been reported. The various problems and

difficulties concerning the migrant labour were discussed in a meeting held with Labour Secretarics of 11 States at New Delhi, on the 21st August, 1982, under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Labour. It was found that a number of States have not framed and notified the Rules under the Inter-State Migrant workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 which made the task of enforcement of the provisions of that Act difficult. It was felt that in the meanwhile a Joint Team of officials of the States concerned, i.e. of the State from where the workers migrate and the State to which they migrate, may meet periodically to deal with certain specific aspects of the problems of migrant labour. It was also suggested that joint studies may be carried out on the actual working and living conditions of the migrant workers by visiting the work-sites to have a first-hand knowledge of the working and living conditions and also to deal with specific complaints. Accordingly, it has been decided to constitute joint study teams consisting of the officials of the Central and the State Governments concerned. The composition of the study teams and the terms of reference will be as under:-

2. Composition :-

Joint Study Team No. I

- (1) Shri S. K. Das, Regional Member-Convener Labour Commissioner (Central) Bombay.
- (2) Representative to be nominated by the Government of Andhra Pradesh.

Member

(3) Representative to be nominated by the Govt. of Maharashtra.

Member

Joint Study Team No. II

(1) Shri O. P. Saxena, Regional Labour Commissioner (C) Chandigarh.

Member-convener

(2) Representative to be nominated by the Government of Bihar, Patna.

Member

(3) Representative to be nominated by the Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.

Member

(4) Representative to be nominated by the Government of Rajasthan, Jaipur.

Member

(5) Representative to be nominated by the Govt. of Punjab, Chandigarh.

Member

- (6) Representative to be nominated by the Govt. of Haryana, Chandigarh. Member
- (7) Representative to be nominated by the Govt. of Himachal Pradesh, Simla.

Member

(8) Representative to be nominated by the Govt. of Jammu and Kashmir, Srinagar. Member

(9) Representative to be nominated by the Delhi

Administration, Delhi.

(10) Representative to be nominated by Government of West Bengal,

Member

Member

(11) Representative to be nominated by Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Calcutta.

Member

3. Terms of Reference of the Joint Study Teams:

The Joint Study Teams (I) and (II) mentioned above will visit the representative States as early as possibble in order to:—

- (i) visit the work-sites of the representative states where migrant workman are employed and in respect of which specific complaints have been received;
- (ii) make an on-the-spot study of the problems of migrant labour with reference to these specific complaints; and
- (iii) carry out general inspection with a view to redressing the other grievances of the migrant workers on the spot, if any (over and above the specific complaints).
- 4. The head quarters of the Teams will be Bombay for Joint Study Team No. I and Chandigarh for Joint Study Team No. II respectively.
- 5. The two Teams will submit their reports, indicating specific remedies to the problems of migrant labour, to the Secretary, Ministry of Labour as early as possible.

S. VENKATARAMAN, Jt. Secy.